राज्य बजट 2026-27 में किसान कल्याण पर विशेष फोकस

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसान कल्याण पर विशेष फोकस रखा है। बजट वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड एक लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राजस्थान को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- रबी दलहनों का उत्पादन 22.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित
- मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित

बजट में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण योजना के तहत 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं नॉन-फार्मिंग सेक्टर के लिए 590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे करीब 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।सिंचाई और खेतों की आधारभूत सुविधाओं के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रस्तावित है। इसके तहत 8 हजार डिग्गियां, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन तथा अगले दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम कृषक संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 50 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में उन्नत बीजों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को मोठ और ज्वार-बाजरा-बरसीम के मिनीकिट वितरित किए जाएंगे। 2.50 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच हजार से अधिक आबादी वाली 3496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में 2098 ग्राम पंचायतों में लगभग 270 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली' विकसित की जाएगी। एआई, एमएल, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य निगरानी और जोखिम प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 'मिशन राज गिफ्ट' भी प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है। 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एनसीआर, यूपी और एमपी में आउटलेट्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित किए गए। नई किस्मों के 31.50 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क दिए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6,206 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवार लाभान्वित हुए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन खरीदने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया।

विधायक रोहित बोहरा ने किया अभद्र इशारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा अभद्र इशारा करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास का मुद्दा उठा रहे थे। रोहित बोहरा उनके पीछे बैठे थे।

इस दौरान बोहरा ने किसी विधायक को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, थोड़ी ही देर में उन्होंने हंसते हुए हाथ से अभद्र इशारा किया था। यह सब विधानसभा की लाइव फीड के कैमरों में भी कैद हो गया था। हालांकि विधानसभा सदन में अब तक किसी विधायक ने इस पर चर्चा नहीं की थी। देर शाम सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर ''बजट राजस्थान 2026-27'' के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। कटारा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दौसा तहसीलदार की कार्यशैली पर विधानसभा में हंगामा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दौसा तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने शून्यकाल के दौरान तहसीलदार पर मनमानी और एससी वर्ग के लोगों के मकान तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार वंचित तबके के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उनका व्यवहार भी अत्यंत खराब है। बैरवा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि पूरे सदन के लिए चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

- कांग्रेस विधायक बैरवा वैल में पहुंचे तो स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

मामले को लेकर सदन में माहौल उस समय गरमा गया जब विधायक बैरवा वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया। उन्होंने बैरवा को मर्यादा में रहने की हिदायत दी और आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की, जिस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि मुख्य सचेतक किस नियम के तहत बीच में हस्तक्षेप कर रहे है।। हंगामे के बीच स्पीकर ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

फैक्ट्री से 1000 किलो सॉस सीज

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान खाद्य सुरक्षा एवं और स्वास्थ्य टीम टीम ने गुरुवार को मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्यवाही कर मिलावट के संदेह पर एक हजार किलो सॉस सीज किया।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री से उत्पादित श्री श्याम ब्रांड सॉस का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाया गया था। जिस पर रिकॉल और रिसेंपलिंग के निर्देश पर टीम इस फैक्ट्री पर पहुंची। मौके पर टीम द्वारा स्नैक्स सॉस और रेड चिली सॉस के नमूने लेकर शेष एक हजार किलो सॉस में कलर मिला होने एवं अन्य कोई मिलावट होने का संदेह होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, सॉस, आचार आदि लगभग 150 किलो एस्पायर पाए गए। जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया।

विधानसभा में फिर गूंजा खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा

विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े प्रकरण भी उठाए

जयपुर (विसं)। राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला प्रमुखता से उठाते हुए इसे प्रदेश की लाइफ लाइन बताया। वहीं अन्य विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

हरीश चौधरी ने कहा कि खेजड़ी का अस्तित्व संकट में है और बीकानेर सहित कई क्षेत्रों में इसके संरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। हम सब इस मामले में विफल रहे हैं, लेकिन अब मिलकर इसे रोकना होगा, उन्होंने कहा। चौधरी ने बताया कि टेनेंसी एक्ट लागू होने के समय खेजड़ी एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन आज यह प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है।

चौधरी ने चर्चा के दौरान एक समाज विशेष का उल्लेख किया, जिस पर विधायक पटेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि उनका नाम लिया जा रहा है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

इस बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए चौधरी को अध्यक्ष को संबोधित करने के निर्देश दिए। टोका-टाकी के बीच चौधरी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो वे नोटिस देकर भी बात करेंगे, लेकिन खेजड़ी का संरक्षण अत्यंत जरूरी है।

17 फरवरी को बजट बहस का जवाब देंगी सरकार

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) ने 19 फरवरी तक का विस्तृत कामकाज तय कर दिया है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में बीएसी का प्रतिवेदन पेश करते हुए आगामी दिनों की कार्यवाही की रूपरेखा साझा की।

बीएसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12, 13, 16 और 17 फरवरी को राज्य बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। इन चार दिनों के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट के विभिन्न प्रावधानों, घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बात रखेंगे।

बजट को लेकर पहले ही सदन में तीखी बहस के संकेत मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में यह चर्चा और तेज होने की संभावना है। आगामी 14 और 15 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही अवकाश के कारण स्थगित रहेगी। इसके बाद 17 फरवरी को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। माना जा रहा है कि वे विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों-कर्ज, घोषणाओं के क्रियान्वयन, सामाजिक योजनाओं और किसानों से जुड़े विषयों-पर सरकार का पक्ष विस्तार से रखेंगी।

फ्री बीज देने में राजस्थान तीसरे नंबर पर : बोहरा

कांग्रेस विधायक ने सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और पिछली बजट घोषणाओं को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बोहरा ने कहा कि जिस 'फ्री बीज' योजना को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जाते थे, उसी मामले में राजस्थान अब देश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, हम पर आरोप लगाते थे, लेकिन आपकी सरकार जीएसडीपी का 14 फीसदी फ्री बीज में दे रही है। हम तो आपसे बहुत पीछे थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट में की गई कई घोषणाएं अब तक अधूरी हैं। बोहरा ने कहा कि एक भी छात्रा को गार्गी पुरस्कार नहीं मिला, बच्चियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर और प्रोत्साहन राशि तक नहीं दी गई। इसके अलावा 5000 अन्नपूर्णा शॉप खोलने की घोषणा पर भी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। कांग्रेस विधायक ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाली 'डबल इंजन सरकार' किसान विरोधी फैसले ले रही है।

बोहरा ने आशंका जताई कि प्रस्तावित अमेरिकी ट्रेड डील से किसानों को भारी नुकसान होगा। उनके अनुसार, यदि सोयाबीन और मक्का अमेरिका से शून्य टैरिफ पर आयात किया गया तो इससे स्थानीय किसानों की फसल और आय पर गंभीर असर पड़ेगा। बजट बहस के दौरान बोहरा के आरोपों को लेकर सदन में हंगामे की स्थिति भी बनी रही।

'नेता प्रतिपक्ष को फॉर्च्यूनर मिलने से हुई डोटासरा को तकलीफ'

भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर कटाक्ष किया

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए वाहन हर सरकार में खरीदे जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर ली गई तो डोटासरा को तकलीफ हो गई। यही फॉर्च्यूनर मंत्रियों के साथ नेता प्रतिपक्ष को भी मिली है। मुझे लगता है उन्हें इस बात से ज्यादा परेशानी है कि नेता प्रतिपक्ष को यह सुविधा कैसे मिल गई।

इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। हंगामे के बीच कैलाश वर्मा ने आपत्ति करने वाले विधायकों से कहा, मुझे क्या बोलना है, यह आप तय नहीं करेंगे, आपको सुनना पडेगा। विपक्ष के विरोध के कारण सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा रहा, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

बजट पर चर्चा के दौरान कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को विरासत में कर्ज का बड़ा बोझ देकर गई है और वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर किया।

6 करोड रुपए के गांजा तस्करी करने वाले को राहत नहीं

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंकाक से करीब छह करोड रुपए के हाईड्रोपोनिक वीड (गांजा) की तस्करी के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश इन्द्रजीत कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि अत्यन्त शक्तिशाली और कई गुणा नशीला हाईड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है। ऐसे मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं।

राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता प्रबंधन पर चर्चा

डीजीपी राजीव शर्मा ने ली पुलिस और पर्यटन विभाग की बैठक

पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरूवार को पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की।

जयपुर। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामों के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डीजीपी ने प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हाल ही में पर्यटन विकास के लिए बजट में दी गई स्वीकृति पर कार्ययोजना तैयार करने व पर्यटन स्थलों पर विशेष त्यौहारों, मेलों के साथ-साथ सामयिक आयोजनों में भी पर्यटन विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य भर के विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा खाटू श्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोगामेड़ी, पुष्करजी, श्रीनाथद्वारा, सांवरियाजी आदि में कुशल प्रबंधन के लिए देवस्थान, पुलिस व प्रशासन मिलकर कार्य करें और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं करें।

बैठक में डीजी (ट्रेफिक) अनिल पालीवाल ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न दूतावासों से संपर्क कर पर्यटन आमंत्रण की बात कही। आईजी अजयपाल लांबा ने डीजी-आईजी कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों को नियोजित करने, एक ही स्थान पर समस्त सरकारी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्यटन स्थलों पर अधिकाधिक सीसीटीवी कवरेज करने, पांच डेस्टिनेशन जहां सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट आते हैं वहां पर्यटन थाना बनाने, ट्यूरिज्म के नेशनल पोर्टल पर राज्यों के पोर्टल को लिंक करने आदि के सुझावों की जानकारी दी। बैठक में पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड ने पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति और यहां पर विभाग द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री, बूथ डिजाइन, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी दी।

खाटूश्यामजी मेले में विशेष प्रबंध करें

डीजीपी शर्मा ने खाटूश्यामजी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटन पुलिस और टीएएफ की ओर से विशेष प्रबंध किए जावें। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह-जगह पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष नंबर, पुलिस हेल्पलाइन 112, राजकॉप सिटीजन एप आदि के लिंक इत्यादि दर्शाती हुई स्टेंडीज व टीएएफ की ओर से विशेष सहायता बूथ स्थाापित करने के निर्देश दिए और कहा कि टीएएफ की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

पर्यटकों को मिले बेहतर सुविधाएं : डीजीपी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आमेर की केस स्टडी में आई अपेक्षाओं को समस्त पर्यटक स्थलों पर लागू करने की बात कही। उन्होंने सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण और आवागमन के लिए व्यवस्थित सड़क सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों के लिए अपेक्षित सूचनाओं की उपलब्धता के संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के साथ-साथ रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सहायता बूथ स्थापित हो जहां पर पर्यटक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संपर्क कर सकें। बैठक में एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) वी.के.सिंह, एडीजी (ट्रेफिक) बीएल मीणा सहित पर्यटन, आरटीडीसी,आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

भजनलाल सरकार का तीसरा बजट ''विकसित राजस्थान'' का रोडमैप : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया।

बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत 6.10 लाख करोड़ रुपये का बजट, वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

अवसंरचना विकास के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ (53 प्रतिशत वृद्धि), शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ (35 प्रतिशत वृद्धि), कृषि बजट में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 400 विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है।

युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 800 करोड़ ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेखावाटी तक यमुना जल लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आधार स्तंभ साबित होगा।